संख्या- 132 /2024/2800/26-3-2024-CN-1397413

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-863-64/स0क0/लेखा-बजट/वि0स्वीकृति/2024-25, दिनांक 12-09-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2235-02-104-02-00 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु पूर्व में निर्गत धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-74/2024/1258/001-1116-26-3-2024-1397413, दिनांक 18.04.2024 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2235-02-104-02-00 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 1000.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-102/2024/2279/26-3-2024-1397413, दिनांक 12.08.2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1666.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 2666.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2235-02-104-02-00 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष **तृतीय किश्त** की धनराशि रू0 1666.00 लाख (रू0 सोलह करोड़ छाछठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2024-25 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर

पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19-06-2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/ स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5)-यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8)-बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता एवं शुद्धता का दायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, समाज कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9)-प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(10) विभाग द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि के संबंध में समय-समय पर नियमानुसार आडिट कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(11) प्रश्नगत योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन,समयावधि एवं नवीनीकरण आदि के संबंध में निदेशक, समाज कल्याण स्व स्तर से संतुष्ट हो लेंगे ।

(12) विभाग द्वारा प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन्स में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(13) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(14) चालू वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान की धनराशि प्रदान की जा रही है के संबंध में अद्यतन आडिट रिपोर्ट का विवरण एक माह के अन्दर वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(15) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा प्रश्नगत योजना के संचालन हेतु जिन स्वैच्छिक संस्थाओं का चयन किया गया एवं उन्हें अनुदान प्रदान किया जा रहा है, के चयन तथा उनके नवीनीकरण आदि के संबंध में विवरण एक माह के अन्दर वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(16) चालू वित्तीय वर्ष,2024-25 में विभाग द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत पूर्व में जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान की धनराशि प्रदान की गयी है, के संबंध में संगत उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुये अनुवर्ती किश्त निर्गत किये जाने हेतु सुसगंत प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,66,00,000 (रुपये सोलह करोड़ छियासठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 080 **लेखा शीर्षक** 2235021040200 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-73-X-2024-25 दिनांक-15-10-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Signed by भवदीय,

Rajani Kant Pandey (रजनी कान्त पाण्डेय)

उप सचिव

Date: 16-10-2024 12:50:56

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7-गार्डफाइल।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव